PUNJAB KESARI, Chandigarh, 28.9.2024
Page No. 3, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

मामला पैरासिटामोल सहित 52 दवाइयों के सैम्पल फेल होने का

खन्ना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा के समक्ष उठाया मुद्दा

होशियारपुर, 27 सितम्बर (जैन): भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि दवाई बनाने वाली कंपनियों द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता के मामले में बरती गई अनियमितता के चलते लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त विचार खन्ना ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा पैरासिटामोल तथा अन्य 52 दवाइयों के टैस्टों को नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित करने के मामले का कड़ा नोटिस लेते हुए इस मामले को पत्र द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाते हुए व्यक्त किए।

खन्ना ने कहा कि अच्छी सेहत सुविधा और स्टैंडर्ड औषधि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ऐसे में दवाइयां बनाने वाली कंपनियों द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता का ध्यान न रखना सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों का हनन है। गुणवत्ता का ध्यान न रखकर दवाइयां बनाने वाली कंपनियां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

खन्ना ने सेहत एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा से मांग की है कि सी.डी.एस.सी.ओ. द्वारा नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित की गई पैरासिटामोल सहित अन्य 52 दवाइयों को बनाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध सख्त करवाई की जाए और अन्य कंपनियों को भी भविष्य में स्टैंडर्ड मैडीसिन क्वालिटी नियमों को ध्यान में रखने की हिदायत की जाए ताकि लोगों को सही गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सकें।

PUNJAB KESARI, Jalandhar, 28.9.2024
Page No. 3, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

मामला पैरासिटामोल सहित 52 दवाइयों के सैम्पल फेल होने का

खन्ना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा के समक्ष उठाया मुद्दा

होशियारपुर, 27 सितम्बर (जैन): भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि दवाई बनाने वाली कंपनियों द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता के मामले में बरती गई अनियमितता के चलते लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त विचार खन्ना ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा पैरासिटामोल तथा अन्य 52 दवाइयों के टैस्टों को नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित करने के मामले का कड़ा नोटिस लेते हुए इस मामले को पत्र द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाते हुए व्यक्त किए।

खन्ना ने कहा कि अच्छी सेहत सुविधा और स्टैंडर्ड औषधि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ऐसे में दवाइयां बनाने वाली कंपनियों द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता का ध्यान न रखना सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों का हनन है। गुणवत्ता का ध्यान न रखकर दवाइयां बनाने वाली कंपनियां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

खन्ना ने सेहत एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा से मांग की है कि सी.डी.एस.सी.ओ. द्वारा नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित की गई पैरासिटामोल सहित अन्य 52 दवाइयों को बनाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध सख्त करवाई की जाए और अन्य कंपनियों को भी भविष्य में स्टैंडर्ड मैडीसिन क्वालिटी नियमों को ध्यान में रखने की हिदायत की जाए ताकि लोगों को सही गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सकें।

PUNJAB KESARI, Ludhiana, 28.9.2024
Page No. 3, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

मामला पैरासिटामोल सहित 52 दवाइयों के सैम्पल फेल होने का

खन्ना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा के समक्ष उठाया मुद्दा

होशियारपुर, 27 सितम्बर (जैन): भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि दवाई बनाने वाली कंपनियों द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता के मामले में बरती गई अनियमितता के चलते लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त विचार खन्ना ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा पैरासिटामोल तथा अन्य 52 दवाइयों के टैस्टों को नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित करने के मामले का कड़ा नोटिस लेते हुए इस मामले को पत्र द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाते हुए व्यक्त किए।

खन्ना ने कहा कि अच्छी सेहत सुविधा और स्टैंडर्ड औषधि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ऐसे में दवाइयां बनाने वाली कंपनियों द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता का ध्यान न रखना सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों का हनन है। गुणवत्ता का ध्यान न रखकर दवाइयां बनाने वाली कंपनियां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

खन्ना ने सेहत एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा से मांग की है कि सी.डी.एस.सी.ओ. द्वारा नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित की गई पैरासिटामोल सहित अन्य 52 दवाइयों को बनाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध सख्त करवाई की जाए और अन्य कंपनियों को भी भविष्य में स्टैंडर्ड मैडीसिन क्वालिटी नियमों को ध्यान में रखने की हिदायत की जाए ताकि लोगों को सही गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सकें।

All's Not Fair In Life And Employment

https://indialegallive.com/magazine/anna-sebastian-perayil-ey-india-work-pressure-corporate-offices-stress/

The case of the recent death of a 26-year-old employee in the offices of EY India due to sheer work pressure has brought out many skeletons from the corporate world. While there are laws to protect employees, their enforcement is weak

September 27, 2024

By Sujit Bhar

In the background of Infosys founder Narayana Murthy's controversial comment about 70-hour work weeks, came the news of the death of an employee of the Pune office of international accounting firm Ernst & Young (EY). The 26-year-old Anna Sebastian Perayil had allegedly died due to an extremely heavy workload and stress.

The office remained unrepentant and it has been said that not a single employee of the firm cared to even attend Anna's funeral. Thereafter, EY India Chairman Rajiv Memani has issued some inane statements that failed to resonate with the general public. In a letter to Memani, a grieving Anna's mother claimed that her daughter died on July 21 after being burdened with a "backbreaking workload" and "work stress". Anna was just four months into her job.

Based on this letter, the Union Labour Ministry ordered a probe and it has now been found that the office was functioning without the state permit that regulates work hours. Since it had opened its offices in 2007, the office had been operating in flagrant disregard of law and without a permit.

According to a report, Maharashtra's Additional Labour Commissioner Shailendra Pol has confirmed that the Pune EY office did not register under the Shops and Establishments Act, which limits working hours to 9 hours per day and 48 hours per week. Pol said: "EY applied for registration only in February 2024, which we rejected because they have been non-compliant since the office opened in 2007." The company

has been given a short notice to explain this lapse.

The issue of this death has travelled further, with the National Human Rights Commission (NHRC) having taken suo motu cognizance of the issue. The NHRC's argument is that if this case has substance, then such issues of severe anxiety, mental stress and lack of sleep tends to affect young workers adversely, violating their basic human rights. A statement from the NHRC said: "It is the prime duty of every employer

to provide a safe, secure and positive environment to its employees. They must ensure that everyone working with them is treated with dignity and fairness."

The NHRC has issued a notice to the Union Ministry of Labour and Employment (this is the oversight ministry, while each state has its own version of the Act), seeking a detailed report within four weeks. The NHRC also wants to know what steps are being taken to prevent recurrence of such incidents.

As the issue stands, the probe and the hullabaloo around the death is bound to see a premature closure in an atmosphere where employee benefits reside at the bottom rung of corporate ladders. This has been aggravated by the nationwide rise in unemployment and through the slide in remuneration levels across the board. While the economy of the country keeps growing at a fast clip, companies show several external factors to snip away at remuneration packages and even in hiring.

Such a disastrous situation was evident recently when a recent report cited a placement crisis at India's top technical institute, the Indian Institutes of Technology (IIT). The report, citing disclosures under the Right to Information (RTI) Act by IIT Kanpur alumnus Dheeraj Singh, said no fewer than 38 percent of IIT graduates across all 23 campuses remain unemployed.

In his Linkedin post, Singh mentioned that 8,000 students failed to secure placements through campus recruitment this year and that this is a sharp increase from two years ago, when the number who failed to find placement was 3,400.

This figure is startling. If this reflects the joblessness that afflicts the top institutes of the country, one can surely imagine the condition of other institutes. It is being believed that organisations, including firms such as EY, are taking full advantage of this situation to drive home to its employees the fact that it is "my way or the highway". While Anna may have succumbed to her condition, there would remain millions of others who remain silent sufferers within this condition.

The positive thing that may emanate from this incident is that laws that had been deemed to have been dead a long time back are slowly being brought back to life. There needs to be awareness of such laws that allow full participation of an employee in the workings of the organisation, within the ambit of law. When we consider the human rights involved, this becomes a larger and more pertinent issue.

It is also pertinent—especially in this particular case—that the women workforce of any office is protected by several employment codes of the Union Labour Ministry and such will have to be followed. With the parents of the deceased stating that they do not wish to pursue further litigation in this issue, maybe several other instances of violation of legal and human rights of Anna would remain unresolved.

With Indian laws able to provide succour, it becomes incumbent on the public to use every sentence of legislation to effect. That is the only way such imbalances in employment may be solved.

EY Employee's Death Sparks Outcry Over Unpermitted Operations of Pune Office Since 2007

https://www.caclubindia.com/news/ey-employees-death-sparks-outcry-over-unpermitted-operations-of-pune-office-since-2007-23880.asp

Last updated: 27 September 2024

The recent dreadful mishap where 26-year-old Anna Sebastian Perayil died at the Ernst & Young (EY) office in Pune raises many questions about the workplace practices of the accounting firm. Official documentations show that EY has been running its operation without a legal state permit, potentially exacerbating issues of employee overload and mental health.

According to a report, a senior government official said that EY, the Pune office of the global audit firm, had been operating since 2007 without obtaining relevant registration under the Shops and Establishments Act under which employers cannot demand more than 9 hours of work in a day and 48 hours in a week. However, the Additional Labour Commissioner of Maharashtra, Shailendra Pol, pointed out that EY had submitted its application for registration only in February 2024 and it was rejected due to non-compliance. The company has now been given a week to respond to the authorities regarding this lapse.

Due to untimely death of Anna, the National Human Rights Commission (NHRC) has taken up the matter of its own accord. The NHRC is highly alarmed by the plight of young employees and all the subjects including mental stress, anxiety and sleep deprivation that is being faced to meet organizational targets. The Commission noted that prevention of discrimination requires employers to ensure that workplaces are free from reckless behaviour, rude or sexual conduct, and that workers and job seekers be respected as individuals. The Union Ministry of Labour and Employment has been asked to submit a detailed report in respect of the steps being taken to prevent such mishaps in future within a period of four weeks.

The Union Labour Ministry has also initiated a probe following Anna's mother's accusations that the company's work culture contributed to her daughter's demise. In a heartfelt letter addressed to EY India Chairman Rajiv Memani, Anna's mother described the immense pressure her daughter endured due to an overwhelming workload during her brief four-month tenure at the firm. She noted that the work culture at EY appeared to glorify overwork while neglecting the well-being of employees, leading to a tragic outcome.

Sibi Joseph, Anna's father, stated that the family does not intend to pursue legal action against the company. Instead, he emphasized the importance of raising awareness to

prevent similar tragedies, asserting that their focus remains on ensuring that no other family has to endure such a loss.

As the investigation unfolds, this incident serves as a stark reminder of the pressing need for corporate accountability in fostering a work environment that prioritizes the health and well-being of employees. The tragic loss of Anna Sebastian underscores the urgent need for companies to evaluate their work cultures and practices, ensuring they align with ethical standards and legal requirements.

NHRC Issues Notice to Odisha Govt Over Villagers' Plight in Keonjhar's Mining Areas

https://odishabhaskar.in/odisha/nhrc-notice-odisha-keonjhar-mining-villagers-tribal-94407/

By SWAGAT On Sep 27, 2024 at 5:13 PM

Bhubaneswar: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to Odisha's Chief Secretary, seeking an Action Taken Report (ATR) on the challenges faced by villagers, particularly tribals and Scheduled Castes, living in the mining-heavy areas of Keonjhar district.

The notice follows a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy, highlighting the adverse living conditions and health issues, such as respiratory and kidney ailments, caused by mining-related environmental pollution. The petition also criticised the state's insufficient response to assist affected communities.

According to the NHRC's statement, mining workers in Keonjhar are subjected to poor living conditions, with no access to essential infrastructure like roads, drinking water, education, or employment opportunities.

The Commission emphasised that the local administration is responsible for the lack of implementation of social welfare schemes, leading to gross violations of the rights of the tribal population.

The NHRC warned that failure to submit the ATR within the stipulated timeframe could lead to coercive action under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, including summoning the concerned authority for a personal appearance.

Odisha, rich in mineral resources, holds about one-third of India's total mineral reserves, with Keonjhar leading in iron ore, coal, bauxite and chromite deposits.

NHRC seeks ATR on plight of Odisha villages in mineral-rich hinterlands

https://www.msn.com/en-in/news/India/nhrc-seeks-atr-on-plight-of-odisha-villages-in-mineral-rich-hinterlands/ar-AA1riwjB#

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notice to the Odisha Chief Secretary and sought for an Action Taken Report (ATR) on the plight of the villagers especially from the tribals and scheduled caste community living in the mineral-rich hinterlands of Keonjhar district

The NHRC sought the ATR while taking cognisance of the petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy.

The quality of life is left much to be desired in the villages bearing the brunt of mining activities. The environmental pollution triggered by mining has led to the outbreak of diseases, including respiratory and renal ailments, to those living on the periphery of areas where lakhs of tonnes of minerals are being extracted on a daily basis, the petition pointed out, adding that the measures on part of the government to extend aid to the affected villagers are largely found wanting.

“The Commission has received a complaint from Radhakanta Tripathy, an advocate and human rights activist from Delhi raising the issue of difficulties being faced by the people in Keonjhar district of Odisha due to mining. The complainant has alleged that the people indulged in mining activities as workers are forced to live in pathetic conditions. There are no proper roads, drinking water, school and employment opportunities for them. The complainant has stated that the administration is solely responsible as no social welfare schemes are functioning in the area and the rights of the people, mostly Scheduled Tribe, are being grossly violated”, the apex rights panel stated in the order.

“The Commission shall be constrained to invoke coercive process u/s 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993 calling for a personal appearance of the authority concerned for submission of the report, in case the report is not received within the stipulated time”, the NHRC added in its order.

Odisha is endowed with vast resources of a variety of minerals and occupies a prominent place in the country as a mineral rich State. Currently, Odisha is endowed with about one third of the estimated national mineral resources.

Keonjhar district leads in State’s mineral reserve. Odisha constitutes 28 per cent iron ore, 24 per cent Coal, 59 per cent Bauxite and 98 per cent Chromite of India’s total deposits, said an official.

NHRC seeks ATR on plight of Odisha villages in mineral-rich hinterlands

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-seeks-atr-on-plight-of-odisha-villages-in-mineral-rich-hinterlands-1503347609.html

The NHRC sought the ATR while taking cognisance of the petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy.

SNS | Bhubaneswar | September 27, 2024 12:39 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notice to the Odisha Chief Secretary and sought for an Action Taken Report (ATR) on the plight of the villagers especially from the tribals and scheduled caste community living in the mineral-rich hinterlands of Keonjhar district.

The NHRC sought the ATR while taking cognisance of the petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy.

The quality of life is left much to be desired in the villages bearing the brunt of mining activities. The environmental pollution triggered by mining has led to the outbreak of diseases, including respiratory and renal ailments, to those living on the periphery of areas where lakhs of tonnes of minerals are being extracted on a daily basis, the petition pointed out, adding that the measures on part of the government to extend aid to the affected villagers are largely found wanting.

“The Commission has received a complaint from Radhakanta Tripathy, an advocate and human rights activist from Delhi raising the issue of difficulties being faced by the people in Keonjhar district of Odisha due to mining. The complainant has alleged that the people indulged in mining activities as workers are forced to live in pathetic conditions. There are no proper roads, drinking water, school and employment opportunities for them. The complainant has stated that the administration is solely responsible as no social welfare schemes are functioning in the area and the rights of the people, mostly Scheduled Tribe, are being grossly violated”, the apex rights panel stated in the order.

“The Commission shall be constrained to invoke coercive process u/s 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993 calling for a personal appearance of the authority concerned for submission of the report, in case the report is not received within the stipulated time”, the NHRC added in its order.

Odisha is endowed with vast resources of a variety of minerals and occupies a prominent place in the country as a mineral rich State. Currently, Odisha is endowed with about one third of the estimated national mineral resources.

Keonjhar district leads in State’s mineral reserve. Odisha constitutes 28 per cent iron ore, 24 per cent Coal, 59 per cent Bauxite and 98 per cent Chromite of India’s total deposits, said an official.

Punjab and Haryana High Court orders immediate reinstatement of civil judge

https://www.tribuneindia.com/news/punjab/punjab-and-haryana-high-court-orders-immediate-reinstatement-of-civil-judge/

After reviewing facts, Bench asserts that decision is unjustified

Saurabh Malik

Tribune News Service

Chandigarh, Updated At : 09:30 PM Sep 27, 2024 IST

The Punjab and Haryana High Court has directed the immediate reinstatement of Nazmeen Singh as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate with continuity of service. The Division Bench of Justice Sureshwar Thakur and Justice Sudeepti Sharma also grant all consequential benefits to the judicial officer, except monetary.

The petitioner had approached the court through senior advocate Puneet Bali with counsel Balwinder Singh and Bhavyashri challenging the decision to dispense with her services on the ground of being unsatisfactory.

The Bench observed that Nazmeen Singh had qualified the Punjab Civil Services judicial examination in 2015 and was appointed as a Civil Judge (Junior Division/Judicial Magistrate) in 2016. Her tenure included postings in Ludhiana and Chandigarh. While stationed in Chandigarh, the Superintendent of Central Jail, Ludhiana, communicated the death of a prisoner at PGIMER due to health complications to UT Chief Judicial Magistrate, requesting an inquest as per the **National Human Rights Commission**'s guidelines.

The Chief Judicial Magistrate, in turn, assigned Nazmeen Singh to conduct inquest proceedings. She constituted a medical board on July 31, 2018, for the autopsy. However, that same day, a complaint was lodged by the medical board members against her, alleging misconduct. The complaint "constituted the bedrock for the impugned order against the petitioner, whereby her services as a probationer were dispensed with".

After reviewing the facts, the Bench asserted that decision was unjustified.

"After completion of the maximum tenure of probationary services by the petitioner, she is deemed to be confirmed against her substantive post. Thereby, there will be an imperative necessity for a full-fledged inquiry being launched against her, for proving the

alleged misconduct. Since the full-fledged inquiry has not been launched, thereby the omission brings to the fore that, the petitioner has been condemned unheard," the court asserted.

The Bench asserted the principles of natural justice were required to be adhered to, especially in matters concerning judicial officers. It was imperative that all relevant parties were heard and that inquiries were conducted fairly and transparently.

Elaborating, the Judges asserted it appeared discreet inquiry was carried behind the petitioner's back. Only one doctor was summoned to testify, who presented electronic evidence from her mobile device, while the other complainants-doctors, were not summoned despite their testimony being crucial at that stage.

Before parting with the order, the Bench added, "The principles of natural justice remain uncomplied with. Therefore, the instant petition is allowed and the impugned order is set aside. The petitioner is ordered to be forthwith reinstated into service with continuity of service and along with all consequential benefits, except monetary benefits," the Bench asserted.

Who's watching the watchers? When police stations themselves become crime scenes

https://www.newindianexpress.com/web-only/2024/Sep/27/whos-watching-the-watchers-when-police-stations-themselves-become-crime-scenes

Despite legal reforms, police stations—meant to be places of protection—are often sites of fear for women.

Sachi Satapathy

Updated on: 27 Sep 2024, 9:10 pm 3 min read

The recent case of police brutality in Odisha, where the fiancée of an Army officer was allegedly assaulted while in custody, has ignited national outrage. But this horrific episode is more than just a singular instance of gender-based violence; it points to systemic flaws in India's law enforcement. Over 2,000 custodial deaths were reported between 2017 and 2021, yet the number of convictions remains staggeringly low.

While the Odisha government's immediate response — suspending officers and promising investigations — may seem swift, these actions appear more aimed at pacifying public anger than delivering real accountability. Without substantial reforms, such measures merely skim the surface, leaving the entrenched culture of police impunity intact.

On the night of September 14-15, a couple approached the Bharatpur Police Station in Odisha to report a road rage incident. Instead of receiving protection, the woman alleges she was brutalized — beaten, molested, and sexually assaulted by officers, including the station inspector. Her fiancé, an Army officer, was also allegedly assaulted and unlawfully detained. This appalling event reveals a disturbing truth: the very institutions designed to protect citizens often become perpetrators of violence.

Beyond the headlines, this case raises critical questions about the state of policing in India. Why do incidents of custodial violence continue to occur with alarming frequency? Why is it so difficult to bring perpetrators to justice? And how can we restore public trust in a system that is meant to protect us?

A 2021-2022 report from the **National Human Rights Commission** documented over 2000 custodial deaths during that period alone, highlighting the widespread abuse of power. Despite efforts like the Supreme Court's 2023 directive mandating CCTV surveillance in police stations, incidents like this one expose glaring gaps in accountability and enforcement.

The pattern of police misconduct then is not unique to Odisha. National Crime Records Bureau (NCRB) data from 2021 reveals that over 49,000 complaints were filed against police officers, yet fewer than 28% resulted in any disciplinary action.

Between 2019 and 2022 less than 1% of officers implicated in custiodial deaths were convicted. The Centre for Law and Policy Research (CLPR) in 2023 highlighted that most of these deaths involved marginalized groups.

In the Odisha case, while five officers have been suspended, such reactive measures barely scratch the surface. What's really needed is to dismantle the entrenched culture of impunity within law enforcement that shields officers from facing meaningful consequences.

Despite legal reforms, such as the 2013 Criminal Law (Amendment) Act aimed at reducing sexual violence, police stations — meant to be places of protection — are often sites of fear for women. In 2022, the NCRB reported over 31,000 cases of rape in India, with a disturbing number involving law enforcement officers as perpetrators. A 2023 report by the Ministry of Women and Child Development revealed that over 70% of women were afraid to report crimes to the police, fearing further mistreatment. This culture of fear silences many victims.

The Odisha case highlights the urgent need for systemic reform. India's response to police misconduct can no longer rely on short-term suspensions or public statements. What is needed is a structural overhaul of the country's law enforcement system. Investigations into police misconduct should be conducted by independent bodies or judicial commissions, not internal police units that often protect their own.

Additionally, India's police forces must undergo continuous gender-sensitivity and human rights training. A 2023 pilot program in Maharashtra, which introduced such training for newly inducted officers, led to a 12% reduction in complaints of police misconduct. This type of training should be scaled up nationwide.

The police departments must also improve transparency by publicly disclosing the outcomes of investigations into misconduct. The custodial deaths and sexual violence perpetrated by law enforcement must lead to swift legal action, with no room for impunity.

The Odisha case has cast a harsh spotlight on India's police forces, exposing the deeply ingrained issues that plague them. The nationwide outrage presents a rare opportunity for meaningful reform, but the question remains: will India seize this moment for change, or will this case simply become another tragic entry in the long list of police brutality incidents? Without systemic reform, the cycle of abuse, impunity, and public mistrust will only continue.

Justice for the Odisha victim — and for all victims of police violence —remains precarious. India's path forward hinges on its willingness to embrace reform. The nation is watching, and what happens next could either pave the way for change or allow the status quo to persist.

ग्वालियरः राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग के स्पेशल रिपोर्टर ने किया ट्रॉ मा सेंटर व अन्य अस्पतालों का निरीक्षण

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/9/27/Special-reporter-of-National-Human-Rights-Commissi.php

27 Sep 2024 20:04:31

ग्वालियर, 27 सितंबर (हि.स.)। ग्वालियर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से **राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग** नई दिल्ली के स्पेशल रिपोर्टर उमेश कुमार शुक्रवार को ग्वालियर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंनेन्हों नेजयारोग्य चिकि त्सालय समूह के ट्रॉ मा सेंटर, कमलाराजा अस्पताल व माधव डिस्पेंसरी पहुँचकर स्वास्थ्य सेवाओं की वस्तुस्थिति जानी। राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग के स्पेशल रिपोर्टर शर्मा ने जयारोग्य अस्पताल समूह के निरीक्षण के दौरान स्पेशल वा र्ड व जर्नल वार्ड का जायजा लिया। साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित इंतजामों की वस्तुस्थिति जानी। उन्होंनेन्हों नेइन व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को उपयोगी सलाह दी। इसके बाद उन्होंनेन्हों नेवहाँ पर ड्यूटी पर काम करने वाली महिला कर्मचारी एवं अस्पताल में इलाज के लिए आईं महिलाओ से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान आयोग मित्र मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग शिकायत प्रकोष्ठ ग्वालियर चम्बल संभा ग डॉ. दीपक शर्मा, जेएएच समूह के अधीक्षक डॉ. सुधीर सक्सेना और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव उनके साथ मौजूद रहे। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोम

दवा बनाने वाली कंपनियों द्वारा जनता की सेहत से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहींः खन्ना

https://www.uttamhindu.com/arvind-kejriwal-raised-questions-in-the-assembly-will-lg-and-mcd-officials-run-delhi-2/

14 hours ago

होशियारपुर(उत्तम हिन्दू न्यूज)- भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि दवाई बनाने वाली कंपनियों द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता के मामले में बरती गयी अनियमितता के चलते लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त विचार खन्ना ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा पेरासिटामोल तथा अन्य 52 दवाइयों के टेस्टों को नॉट स्टैण्डर्ड क्वालिटी घोषित करने के मामले का कड़ा नोटिस लेते हुए इस मामले को पत्र द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा तथा **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के समक्ष उठाते हुए व्यक्त किये।

खन्ना ने कहा कि अच्छी सेहत सुविधा और स्टैण्डर्ड औषधि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ऐसे में दवाइयां बनाने वाली कंपनियों द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता का ध्यान न रखना सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों का हनन है। गुणवत्ता का ध्यान न रखकर दवाइयां बनाने वाली कंपनियां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहीं हैं। खन्ना ने सेहत एवं परवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा से मांग की है कि सी.डी.ऐस.सी.ओ. द्वारा नॉट स्टैण्डर्ड क्वालिटी घोषित की गयी पेरासिटामोल सहित अन्य 52 दवाइयों को बनाने वाली वाली कंपनियों के विरुद्ध सख्त करवाई की जाए और अन्य कंपनियों को भी भविष्य में स्टैण्डर्ड मेडिसिन क्वालिटी नियमों को ध्यान में रखने की हिदायत की जाये ताकि लोगों को सही गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सकें।

भारत के हर छठवें पुलिस थाने में अब भी नहीं लगे हैं सीसीटीवी कैमरे

https://hindi.latestly.com/india/cctv-cameras-are-still-not-installed-in-every-sixth-police-station-in-india-2325352.html

ओडिशा के एक थाने में हुई यौन उत्पीड़न की घटना ने सीसीटीवी कैमरों की सख्त जरूरत की ओर ध्यान दिलाया है.

ओडिशा के एक थाने में हुई यौन उत्पीड़न की घटना ने सीसीटीवी कैमरों की सख्त जरूरत की ओर ध्यान दिलाया है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा रोकने के लिए सीसीटीवी जरूरी हैं.बीते दिनों ओडिशा से एक परेशान करने वाली खबर आई. एक महिला ने आरोप लगाया कि राजधानी भुवनेश्वर के एक पुलिस थाने में उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया. कथित घटना 14-15 सितंबर की दरमियानी रात को हुई. महिला कुछ युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन गई थीं. उनके साथ उनके मंगेतर भी थे, जो सेना में अधिकारी हैं.

महिला ने मीडिया से कहा, "थाने में मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. बल्कि मेरे मंगेतर को कस्टडी में डाल दिया. विरोध करने पर दो महिला अफसरों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया. जैकेट से मेरे हाथ बांध दिए और एक स्कॉर्फ से पैर बांधकर मुझे कमरे में डाल दिया. इसके बाद एक पुरुष अधिकारी ने मेरी छाती पर लातें मारीं. फिर स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक आए और उन्होंने मेरा और खुद का पैंट नीचे कर दिया और मुझे अपना लिंग दिखाकर भद्दी बातें कीं."

शौचालय के जरिए सम्मान की लड़ाई लड़ रहीं भारतीय महिलाएं

पुलिस ने तब महिला को गिरफ्तार भी कर लिया था. महिला को 18 सितंबर को ओडिशा हाईकोर्ट से जमानत मिली. उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर पुलिस पर यह आरोप लगाए. इस मामले में थाने के प्रभारी निरीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

पुलिस स्टेशन में नहीं लगे थे सीसीटीवी कैमरे

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भरतपुर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का उद्घाटन इसी साल मार्च में हुआ था. लेकिन उसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे. मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने कहा है कि कैमरे ना होने की वजह से सबूत जुटाने में दिक्कत आएगी. ओडिशा हाईकोर्ट ने भी थाने में सीसीटीवी कैमरे ना होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस वजह से सच्चाई सामने नहीं आ सकी. हाईकोर्ट ने राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश भी दिया.

इसके बाद ओडिशा के पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया ने कहा है कि आठ अक्टूबर तक राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे. दरअसल, पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों का होना कानूनी रूप से जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे.

जस्टिस आरएफ नरीमन, केएम जोसेफ और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए.

जानकारों के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा पर लगाम लगाना था, जिससे फरियादियों और आरोपियों दोनों के मानवाधिकार सुरक्षित रहें**. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के मुताबिक, पूरे देश में साल 2018 से 2023 के बीच पुलिस हिरासत में हुई मौतों के संबंध में 650 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. सबसे ज्यादा मामले गुजरात (81) और महाराष्ट्र (80) में दर्ज हुए. इसके अलावा एमपी में 50, यूपी में 41, पश्चिम बंगाल में 40 और तमिलनाडु में 36 मामले सामने आए.

देश के तीन हजार थानों में नहीं लगे सीसीटीवी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, अभी तक देश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं. ओडिशा का भरतपुर थाना इसका ताजा उदाहरण है. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के डेटा के मुताबिक, एक जनवरी, 2023 को देशभर में करीब 18 हजार पुलिस थाने थे. इनमे से करीब 15 हजार पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे थे और करीब तीन हजार थानों में नहीं थे. यानी देश के हर छठवें पुलिस थाने में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी. वहीं, ओडिशा की बात करें तो एक जनवरी 2023 को वहां कुल 679 पुलिस थाने थे, जिनमें से 88 थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे.

इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों की पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी कैमरों की संख्या में भी भारी अंतर है. डेटा के मुताबिक, एक जनवरी 2023 को देश भर में पुलिस के पास करीब साढ़े पांच लाख सीसीटीवी कैमरे थे. इनमें से करीब दो लाख 80 हजार कैमरे सिर्फ तेलंगाना पुलिस के पास थे. वहीं ओडिशा पुलिस के पास सिर्फ 780 सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे. इसके अलावा असम, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड आदि राज्यों में भी पुलिस के पास हजार से कम सीसीटीवी थे.

थाने में किन जगहों पर सीसीटीवी जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, थानों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे चौबीसों घंटे चलने चाहिए. उनमें और एक स्कॉर्फ से पैर बांधकर मुझे कमरे में डाल दिया. इसके बाद एक पुरुष अधिकारी ने मेरी छाती पर लातें मारीं. फिर स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक आए और उन्होंने मेरा और खुद का पैंट नीचे कर दिया और मुझे अपना लिंग दिखाकर भद्दी बातें कीं.”

शौचालय के जरिए सम्मान की लड़ाई लड़ रहीं भारतीय महिलाएं

पुलिस ने तब महिला को गिरफ्तार भी कर लिया था. महिला को 18 सितंबर को ओडिशा हाईकोर्ट से जमानत मिली. उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर पुलिस पर यह आरोप लगाए. इस मामले में थाने के प्रभारी निरीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

पुलिस स्टेशन में नहीं लगे थे सीसीटीवी कैमरे

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भरतपुर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का उद्घाटन इसी साल मार्च में हुआ था. लेकिन उसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे. मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने कहा है कि कैमरे ना होने की वजह से सबूत जुटाने में दिक्कत आएगी. ओडिशा हाईकोर्ट ने भी थाने में सीसीटीवी कैमरे ना होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस वजह से सच्चाई सामने नहीं आ सकी. हाईकोर्ट ने राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश भी दिया.

इसके बाद ओडिशा के पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया ने कहा है कि आठ अक्टूबर तक राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे. दरअसल, पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों का होना कानूनी रूप से जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे. जस्टिस आरएफ नरीमन, केएम जोसेफ और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए.

जानकारों के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा पर लगाम लगाना था, जिससे फरियादियों और आरोपियों दोनों के मानवाधिकार सुरक्षित रहें. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक, पूरे देश में साल 2018 से 2023 के बीच पुलिस हिरासत में हुई मौतों के संबंध में 650 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. सबसे ज्यादा मामले गुजरात (81) और महाराष्ट्र (80) में दर्ज हुए. इसके अलावा एमपी में 50, यूपी में 41, पश्चिम बंगाल में 40 और तमिलनाडु में 36 मामले सामने आए.

देश के तीन हजार थानों में नहीं लगे सीसीटीवी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, अभी तक देश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं. ओडिशा का भरतपुर थाना इसका ताजा उदाहरण है. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के डेटा के मुताबिक, एक जनवरी, 2023 को देशभर में करीब 18 हजार पुलिस थाने थे. इनमे से करीब 15 हजार पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे थे और करीब तीन हजार थानों में नहीं थे. यानी देश के हर छठवें पुलिस थाने में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी. वहीं, ओडिशा की बात करें तो एक जनवरी 2023 को वहां कुल 679 पुलिस थाने थे, जिनमें से 88 थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे.

इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों की पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी कैमरों की संख्या में भी भारी अंतर है. डेटा के मुताबिक, एक जनवरी 2023 को देश भर में पुलिस के पास करीब साढ़े पांच लाख सीसीटीवी कैमरे थे. इनमें से करीब दो लाख 80 हजार कैमरे सिर्फ तेलंगाना पुलिस के पास थे. वहीं ओडिशा पुलिस के पास सिर्फ 780 सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे. इसके अलावा असम, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड आदि राज्यों में भी पुलिस के पास हजार से कम सीसीटीवी थे.

थाने में किन जगहों पर सीसीटीवी जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, थानों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे चौबीसों घंटे चलने चाहिए. उनमें नाइट विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए. साथ ही कम से कम साल भर की फुटेज सुरक्षित रखने की क्षमता होनी चाहिए. थानों के सभी प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी होने चाहिए.

इसके अलावा सभी हवालात, गलियारे, बरामदे, रिसेप्शन एरिया, निरीक्षक और उप-निरीक्षक के कमरे और शौचालयों के बाहर की जगह भी कैमरों की जद में आनी चाहिए.

ओडिशा में कैसे हुई पुतिन के आलोचक की रहस्यमय मौत

शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर निरीक्षण समितियां बनाई जाएं, जिनमें उच्च अधिकारी शामिल हों. सीसीटीवी कैमरों के संचालन, निगरानी और रखरखाव का जिम्मा जिला स्तरीय निगरानी समिति के पास होगा. यह समिति थानों के सीसीटीवी फुटेज देखकर यह भी पता लगाएगी कि किसी थाने में मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है. वहीं, राज्य स्तरीय निगरानी समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह जिलों से आने वाली शिकायतों का निपटारा करे.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पुलिस थाने में बल प्रयोग के चलते किसी को गंभीर चोट आती है या हिरासत में मौत होती है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार अदालतों में इसकी शिकायत की जा सकती है. इसके बाद आयोग या अदालत तुरंत घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज मंगवा सकती है, जिससे उसे सुरक्षित रखा जा सके और बाद में आगे की कार्रवाई के लिए जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सके.